

इतने से कर्मचारियों के लिये रेंट देते रहे और उन को प्लाट नहीं दिया। जो प्लाट उनके लिये रखा गया था वह कांग्रेस को बाद में दे दिया गया और अभी तक उनकी प्लाट अलौट नहीं हुआ है। तो क्या जो उनके लिये पहले से प्लाट था वह उसका रेस्टोर कराया जायगा और जो इतने दिनों तक रुपया पड़ा रहा जिस पर बक्स मन्त्रालय से इंटररेस्ट नहीं मिला, वह इंटररेस्ट भी दिलायेंगे ?

SHRI RAVINDRA VARMA: Sir, as the hon. Member has said, on two occasions, land was allotted for the purpose, but, unfortunately, on both the occasions, the allotment was cancelled. In one case, the land was near Lodi Road which was cancelled, for one reason or another. In another case, the land was near the Barakhamba Lane, which too was cancelled after allotment was cancelled. I do not know whether it was cancelled so that the land might be given to the Congress Party, but it was not a part of the question. As far as the other question he asked is concerned, it is true that after receiving allotment, the Provident Fund organisation spent quite a lot of money both to pay for the premium of the land and also for abolition of some of the buildings that existed there so that construction might take place. Rs. 3.30 lakh has been paid to the Government and the Government has been requested for reimbursement of this amount and the interest but that has not been paid yet. Now, in view of what the hon. Member has said I can make an enquiry and find out whether it is a fact that the allotment was cancelled so that it might be given to somebody else.

श्री शिव नारायण सरसूनिया : उनको इंटररेस्ट नहीं मिला जो रुपया इतनी देर तक पड़ा रहा, यह मैंने पूछा था। उस बारे में आपका क्या विचार है। दूसरे यह कि क्योंकि उनको पैसे नहीं दिया गया वह प्लाट किसिल करके कांग्रेस को दिया गया।

SHRI RAVINDRA VARMA: I have answered and said that this amount has not been returned in spite of the requests.

श्री राम मूर्ति : मन्त्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय के स्तर पर कोई कमेटी बना दी जाय जो इस तरह के केसेज का निरीक्षण करे और भविष्य में इस तरह पैसे की बरबादी न हो इस बारे में विचार करेंगे ?

SHRI RAVINDRA VARMA: This is a suggestion.

Non-use of National language for official work in Indian Embassies abroad

*266. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a foreign language viz., English is used by India for official work as well as in propagating Indian culture;

(b) whether foreigners ridicule us for using a foreign language and for neglecting national languages of India viz., Hindi, Bengali, Tamil Marathi etc. if so, the immediate steps proposed to be taken for changing this practice;

(c) whether the higher officers in Indian embassies deliberately neglect the national language because in India itself it is not shown due respect; and

(d) if so, the steps being taken by Government in this direction?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) हिन्दी का प्रयोग प्रगामी रूप से बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन इस समय विदेश स्थित हमारे मिशन में कामकाज में व्यापक रूप से अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता है।

(ख) अंग्रेजी के प्रयोग की वजह से कहीं उपहास किये जाने की कोई घटना तो हमारी जानकारी में नहीं आयी है, लेकिन राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को अत्यधिक प्रोत्साहन देना सरकार की नीति है।

(ग) और (घ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को स्थाई होने से पहले राज-भाषा की एक विभागीय परीक्षा पास करनी होती है। भारत की राष्ट्रीय-भाषाओं के प्रति किसी तरह का कोई अनादर नहीं दिखाया गया है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या मन्त्री महोदय को यह बात पता है कि नेपाल, जिसकी अपनी भाषा की लिपी भी देवनागरी है, उस को भारत सरकार की जितनी भी मदद मिली है, उन सारी कार्यवाहियों के अंग्रेजी में होने के कारण नेपाल से हिन्दी की पढ़ाई प्रायः समाप्त हो गई है, और उन लोगों को बाध्य होकर अंग्रेजी पढ़ने के लिये स्कूल और कालेजों में व्यवस्था करनी पड़ी है ?

जैसा कि आपने कहा दूतावासों में उपेक्षा भी है हीं, कुछ लोग हिन्दी का व्यवहार भी करना चाहते हैं तो उन को टंकण की आपूर्ति भी नहीं की जाती है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार की नीति, भारत में और भारत के बाहर भी, हिन्दी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ावा देने की है। विदेशों के साथ जो संधियां होती है, अब अंग्रेजी के साथ उन्हें हिन्दी में भी किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : कब से।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : काफी समय हो गया।

विदेशों में जो हमारे मिशन है, उन के नामों के पट्टे हिन्दी और अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषाओं में रहे, इस तरह के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। हमारे राजदूत, गैर-अंग्रेजी भाषी देशों में जब अपने परिचय पत्र पेश करते हैं तो उन से कहा गया है कि वे हिन्दी में बोले,

क्योंकि अंग्रेजी में बोलने के बाद भी उसका अनुवाद करना पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि वह हिन्दी का प्रयोग करें।

जहां तक नेपाल का संबंध है, नेपाल और भारत के बीच में कोई भाषा संबंधी कठिनाई पैदा नहीं होनी चाहिये। जो परियोजनायें हमने नेपाल में शुरू की हैं, और जहां हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन के बच्चों के लिये केन्द्रीय विद्यालय चन रहे हैं, जिसमें हिन्दी के पठनपाठन की पूरी व्यवस्था है। अगर माननीय सदस्य को कोई विशेष शिकायत हो तो बता सकते हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मेरा सवाल यह है कि भारत सरकार उन परियोजनाओं को जमाने में जो मदद करती है और जो काम होता है वह अंग्रेजी में करती है जिसके कारण उन्हें हिन्दी की पढ़ाई से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिये बाध्य होना पड़ा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न समझने में मैं अममर्थ हूँ कि हम अपना काम अंग्रेजी में करते हैं, इसलिए उन्होंने हिन्दी की पढ़ाई छोड़ दी है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : भारत सरकार की मदद पर नेपाल सरकार के काम चलते हैं। सारा का सारा काम अंग्रेजी में होने के कारण, जो हिन्दी की पढ़ाई करते थे, वह भी हिन्दी छोड़ चुके हैं, क्योंकि हिन्दी का उपयोग नहीं होता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कहना ठीक नहीं होगा कि नेपाल का सारा कामकाज हमारी मदद से चल रहा है। हम नेपाल को सहायता दे रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : आपकी सरकार अंग्रेजी में काम क्यों करती है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी संसद् ने जो कानून बनाया है, उसके अनुसार

हिन्दी और अंग्रेजी दोनों राजकीय भाषाएं हैं। जो कर्मचारी हिन्दी में काम करना चाहते हैं, उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं है, मगर हम किसी को हिन्दी में काम करने के लिए विवश नहीं कर सकते। अगर संसद् चाहे तो यह कानून बदल सकती है और सरकार उसका पालन करे।

श्री मनीराम बागड़ी : अभ्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

मंत्री महोदय ने यह बात कही है कि हिन्दी और अंग्रेजी। वे यह कह सकते हैं कि गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के अन्दर वे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप हिन्दी में काम करें। लेकिन यह नहीं कह सकते कि अंग्रेजी चले, उसको न रोका जाये। संविधान की यह इच्छा है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा एक निश्चित काल में बनावें और सरकार उस रास्ते पर नहीं चलती। मंत्री महोदय ने हिन्दी के विरोध में और राष्ट्रभाषा के विरोध में बयान दिया है।

MR. SPEAKER: There is no point of order in that.

Mr. Yadav will put his second question.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मंत्री महोदय ने बताया है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हिन्दी के प्रयोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। नागपुर और मारीशस में होने वाले दो विश्व हिन्दी सम्मेलनों में प्रतिनिधियों ने यह आकांक्षा प्रकट की है कि हिन्दी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बने, लेकिन इसकी पहल भारत सरकार को करनी पड़ेगी। इस विषय में सरकार की क्या नीति है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब से विदेश मंत्रालय का भार मैंने संभाला है, उसमें हिन्दी का प्रयोग काफी बढ़ा है। पहली बार

विदेशी मेहमानों से, जो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, मैंने हिन्दी में बातचीत करना प्रारम्भ किया है। जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को लाने का प्रश्न है, मैं तो चाहूंगा कि वहां हिन्दी आये और मेरी इच्छा है कि वहां पर मैं पहला भाषण हिन्दी में करूँ। लेकिन वित्त मंत्रालय को मेरी मदद के लिए आना होगा—6 करोड़ रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन आत्म-सम्मान की दृष्टि से यह खर्चा अधिक नहीं है। अगर सदन सारा जोर लगा कर वित्त मंत्री से कहे, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

SHRI A. E. T. BARROW: I am grateful to the Hon. Minister Shri Vajpayee for not accepting that English is a foreign language. I would ask him to remember that English is the mother-tongue of my Community which is an Indian community and, therefore, it is the mother-tongue of the Indian community and not a foreign language.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, no question has been put.

श्री जनेश्वर मिश्र : मंत्री महोदय ने कहा है कि विदेशों में भारत के जो दूतावास हैं, वहां भारतीय भाषाओं को, और विशेषकर हिन्दी को, ज्यादा प्रोत्साहन दिया जायेगा। हमारे जो राजदूत या उच्चाधिकारी, जो जो हिन्दी जानते हैं, और जान-बूझ कर विदेशी नक्शेबाजी के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, क्या विदेश मंत्री उन के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? मंत्री महोदय ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना प्रथम भाषण हिन्दी में देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वित्त मंत्री की मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या माननीय वित्त मंत्री ने उसके संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में बोलने के कारण जो खर्चा बढ़ रहा है, वह खर्चा देने से इन्कार किया है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दे दूँ। अभी न तो

इन्कार किया है और न इकरार किया है। पामला त्वेजन्सपीक है। जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है, हमारे राजदूत अंग्रेजीमय वातावरण की उपज हैं। मुझे यह देख कर खेद हुआ कि जिन देशों में अंग्रेजी नहीं चलती है, जहां अरबी, फ्रेंच या स्पेनिश चलती है, वहां भी हमारे अनेक राजदूत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे राजदूत जिस देश में रहें, वहां की भाषा को जानें और उसका प्रयोग करें। हिन्दी जानने वाले जब उनसे बात करने के लिए आते हैं, तो वे हिन्दी में बोलें। लेकिन मैं सच्चा से प्रारम्भ नहीं करना चाहता हूँ। पहले मैं समझाने-बुझाने से काम लेने में विश्वास करता हूँ।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: May I know whether the intention of the Government is that our Embassies in foreign countries should use whichever language they understand so that we can carry on our business in those countries, rather than impose Hindi on them as is being attempted in India today, and also to avoid such a situation as was cartooned in yesterday's *Times of India* about a letter being sent to the Kerala Government in Hindi and the reply being given in Malayalam?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: There is no intention of imposing Hindi on any part of India. But I would like my non-Hindi speaking friends to understand that they should not impose English either on any part of the country. No imposition either of Hindi or of English. Those who want to work in Hindi should be free to do so.

So far as foreign embassies are concerned, our attempt is that they should work in the language of the country in which they are stationed.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गैर-अंग्रेजी भाषी जितने देश हैं जहाँ पर फ्रेंच, स्पेनिश

या अरबी बोली जाती है, वहाँ के हमारे राजदूतावासों में जितने दुभाषिये हैं वे भी सिर्फ अंग्रेजी और उस देश की भाषा में बात करते हैं, तो कम से कम उन देशों में जहाँ पर कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, अंग्रेजी में बात नहीं करता, जो हमारे दुभाषिये रखे जायें वे तो ऐसे होने चाहिएँ जो हिन्दी और उस देश की भाषा में बात कर सकें और उसे समझने हों, क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि वहाँ पर ऐसे दुभाषिये रखे जाएँगे जो उस देश की भाषा और हिन्दी में बात कर सकें ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सचार्ई तो यह है कि विदेश मंत्रालय में अभी तक दुभाषियों का इन्तजाम करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। जब मैंने विदेशी मेहमानों से बात करने का निश्चय किया और दुभाषियों की आवश्यकता पड़ी तो हमारा मंत्रालय दुभाषिये नहीं दे सका, इसलिए हमें किसी विश्वविद्यालय से या बाहर से प्राशक्षण प्राप्त दुभाषियों का उपयोग करना पड़ा। विदेशी दूतावासों में भी हम चाहते हैं कि दुभाषिये रहें और वे ऐसे दुभाषिये हों जो हिन्दी से अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश आदि में भाषान्तर कर सकें। अभी तक इसका प्रबन्ध नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी किया जाये, यह हमारी कोशिश है।

SHRI A. C. GEORGE: The Gulf countries, of late, are developing as the most potential territories in our international relations. It is widely known that a very sizeable majority of the population of Indians in the Gulf countries are from Kerala and now-a-days even the rulers and the Sheikhs are understanding Malayalam language. Will the hon. Minister kindly see that the Embassies in these countries use Malayalam as the official language?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I do not know, if the hon. Member is making this suggestion seriously. I can

I understand one member of the staff knowing Malayalam language in order to deal with those people who go from Kerala, but the entire mission cannot conduct its business in Malayalam.

श्री रूपनाथ सिंह यादव : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की इतनी बड़ी आबादी में कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी जानकारी नहीं देना चाहता जो गलत साबित हो और इसलिए मुझे सूचना मिले तो मैं सही जानकारी एकत्र करके इसका उत्तर दे सकूंगा ।

Many hon. Members rose.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: We send our questions and our names come in the ballot, but we do not get a chance because the priority in the Question List may be low. I would, therefore, request that more questions may be covered in the Question Hour.

MR. SPEAKER: How can I stop Members wanting to ask questions which they consider important?

Now, Shri Chandrappan.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: I would like to know from the hon. Minister whether it is necessary at all to take a very rigid stand on the language which our personnel employed in the Embassies should follow because there are, as I understand, languages which are internationally accepted by the United Nations for dealing in international matters. I think without taking a rigid position if the Government takes the position that a practical point of view will be taken in so far as language is concerned, it will help the country. Will the Minister accept this suggestion? That is my question.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: The suggestion will be given due consideration.

MR. SPEAKER: May I now go to the next question because there are a number of important questions? If all of you get up, I am helpless.

नर्सों से प्रतिभूति राशि लिया जाना

* 267. श्री हरगोविन्द वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशिक्षण काल में नर्सों से ली जाने वाली प्रतिभूति राशि न लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठना ।

श्री हरगोविन्द वर्मा : मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था न होने से नर्सों की ट्रेनिंग में बहुत दिक्कत हो रही है । आज पूरे देश में नर्सों और कम्पाउण्डर्स की बहुत कमी है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग में बहुत दिक्कत हो रही है । अस्पतालों में जाइये तो वहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती है, मरीज खड़े रहते हैं— मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री राजनारायण : - वास्तव में मुल्क के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है । नर्सों को प्रशिक्षित करने के लिये जिन-जिन मुख्य पाठ्यक्रमों को आयोजित किया जाता है, वे इस प्रकार हैं :—

1. जनरल नर्सिंग,

2. वार्ड सिस्टर-कम-सिस्टर टियुटर कोर्स,